P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-8* April- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण लखनऊ परिमण्डल/क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में

Financial Statement Analysis of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Special Reference Lucknow Region (Period 01-04-2018 to 31-03-2019)

Paper Submission: 05/04/2021, Date of Acceptance: 15/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

संजीव कुमार
शोधार्थी,
वाणिज्य विभाग,
ए0 के0 पी0 जी. कॉलेज,
बी0 आर0 अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा,
शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

गिरिराज कुमार गुप्ता
रिटायर्ड प्रिन्सिपल,
वाणिज्य विभाग,
ए0 के0 पी0 जी. कॉलेज,
बी0 आर0 अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा,
शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रमीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। ग्रामीण भारत की बैकिंग आवश्यकताएं इस दृष्टि से अनुपम है, कि ऋण आवश्यकताएं छोटी होती है। और बार–बार लेन देन करना होता है। इस कारण बैंको की लेन देन लागत बढ़ जाती है। जिससे बैंक ग्रामीण क्षेत्रो में जाने से झिझकते है। इससे ग्रामीण ग्राहको को भी कठिनाई होती है, नाबार्ड द्वारा प्रचलित किए गये स्वयं सहायता समूह (SHG) ने इस समस्या का प्रभावी समाधान खोज निकाला है। यह बचत और ऋण संवितरण के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली विकल्प बन गया है। देश में लगभग 80 लाख एस एच जी है, जिसमें 8 करोड़ से अधिक महिलाएं है, जो इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है।

बैंको को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को अपने व्यापार बढ़ाने का एक साधन मानकर चलना पड़ेगा। वास्तविकता भी यही है कि दूर–दूर गॉव तक बैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हुए बैंक अपनी बचत एवं ऋणों को बढ़ाकर अपने व्यापार बढ़ा सकते है। इससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार बढ़ेगा एवं अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसके अलावा बीमा, माइको पेंशन और धन प्रेषण को बैकिंग सेवाओं का हिस्सा बनाकर ग्रामीण क्षेत्रो में ले जाने की आवश्यकता है। देश के समाविष्ट आर्थिक विकास के लिए पूर्ण वित्तीय समावेशन अत्यंत आवश्यक है।

National Bank for Agriculture and Rural Development is such a bank which provides loans to the rural people for their development and financially to improve their standard of living. The banking needs of rural India are unique in that the credit requirements are small. And you have to do frequent transactions. Due to this, the transaction cost of the banks increases. Due to which banks are hesitant to go to rural areas. This also causes hardship to rural customers, Self Help Groups (SHGs) promoted by NABARD have found an effective solution to this problem. It has become a very effective option for savings and loan disbursement. There are about 80 lakh SHGs in the country, of which more than 80 million are women, which shows the popularity of this scheme.

Banks will have to treat the financial inclusion program as a means of increasing their business. The reality is also that banks can increase their business by increasing their savings and loans by providing banking services to remote villages. This will increase employment in rural areas and the economy will develop. Apart from this, there is a need to take insurance, micro pension and remittance to rural areas by making them a part of banking services. Full financial inclusion is essential for the inclusive economic development of the country.

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का इतिहास, शोध के उद्देश्य, नाबार्ड की भूमिका, नाबार्ड के लखनऊ क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में, चालू अनुपात, स्कन्ध अनुपात, तरलता अनुपात, स्वामित्व अनुपात आदि।

History Of National Bank For Agriculture And Rural Development, Objectives Of Research, Role Of NABARD, With Special Reference To NABARD's Lucknow Region, Current Ratio, Inventory Ratio, Liquidity Ratio, Ownership Ratio Etc.

प्रस्तावना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का इतिहास

1. शिवरामन समिति (शिवरामन कमैटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी) तथा कृषि पुनर्वित और विकास निगम (एआरडीसी) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई यह ग्रामीण क्षेत्रो में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।

   राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रमीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है।

   कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पो के उन्नयन और विकास के लिए ऋण–प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रो में अन्य संबंधित कियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढावा देने और ग्रामीण क्षेत्रो में समृद्वि सुनिश्चित करने का अधिदेश पास है।
2. नाबार्ड का पुनर्वित राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और आरबीआई अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध है। जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों, साझेदारी के संबधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमो, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है।

   नाबार्ड का अपना मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुम्बई, महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है, इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रो में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलो में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

   नाबार्ड अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालय और एक उप कार्यालय जो सभी राज्यों/केन्द्र शाषित प्रदेशो की राजधानियों में स्थित है, के माध्यम से देश भर में परिचालित है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान कार्यकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबन्धक (सीजीएम) है और प्रधान कार्यालय में कई शीर्ष अधिकारी कार्यकारी होते है। जैसे कि कार्यकारी निदेशक (ईडी), प्रबंध निर्देशकों (एमडी) और अध्यक्ष, सम्पूर्ण देश में इसके 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप–कार्यालय और श्रीनगर में एक सेल है। इसके पास 6 प्रशिक्षण संस्थान भी है।

   नाबार्ड को इसके एसएचजी (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए भी जाना जाता है जो भारत के बैंको को समूहों एसएचजी (SHGs) उधार देने के लिए प्रोतसाहित करता है। क्योंकि एसएचजीज का गठन विशेषकर गरीब महिलाओं को लेकर किया गया है, इससे यह माइक्रोफाइनांस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्च 2006 तक 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2200000 लाख स्वयं सहायता समूह ऋण से जुड चुके थे।

   यह एक शीर्ष बैंकिग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुंजी उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 100 करोड रूपये की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी। 2010 में नाबार्ड की प्रदत्त राशि 2000 करोड रूपये पर पहुंच गई। यह ग्रामीण ऋण संरचना की एक शीर्ष संस्था है जो कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प आदि को बढावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।

अध्ययन के उद्देश्य

वित्तीय विवरणों में अंकित समंकों व समाहित तथ्यों के आधार पर संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकार (अंशधारी, लेनदार, बैंक, ऋणदाता, सरकार, कर अधिकारी व अन्य) विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न प्रकार का निर्णय लेते हैं, जिनमें कि इन विवरणों का उद्देश्य और अधिक व्यापक हो जाता हैं, अतः वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. ऐसी सूचना प्रदान करना जिनसे वर्तमान एवं भावी विनयोजक विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकें।
2. ऐसी सूचना प्रकट करना जिनके आधार पर प्रतिभूतियों के शोधन, आय–अर्जन तथा लाभांश घोषणा दर/प्रतिफल के वारे में सूचना दे सकें।
3. व्यवसायिक संस्था के आर्थिक संसाधनों की जानकारी उपलब्ध होना।
4. भावी रोकड़ अन्तर्वाह एवं बहिर्गमन की जानकारी होना।
5. कृषि बुनियादी ढॉचे और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना
6. ग्रामीण विकास हेतु अनुकूल नीतियों, पध्दतियों एवं नवोन्मेषी प्रणालियों का संवर्धन

नाबार्ड की भूमिका

1. यह एक शीर्ष संस्था है जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण देने के साथ–साथ नीति से संबंधित सभी मामलों से निपटने की योजना बना करने की शक्ति है, जो एक शीर्ष संस्था है।

2. यह उन संस्थाओं के लिए एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है जो ग्रामीण विकास के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करते है।
3. यह भारत में निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के निर्माण, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, और कर्मियों के प्रशिक्षण सहित भारत में ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता में सुधार करता है।
4. यह जमीनी स्तर पर विकास कार्यो में लगे संस्थानों के लिए सभी प्रकार की ग्रमीण वित्तपोषण गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है और नीति निर्माण से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकारों, और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है।
5. यह देश के सभी जिलों के लिए सालाना ग्रामीण ऋण योजनाओं का तैयार करता है।
6. यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान, और कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।

नाबार्ड के लखनऊ क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में

बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ नाबार्ड द्वारा संबन्धित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, बर्ड के अन्तर्गत स्थापित सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस (सीएमआर) ''दि माइक्रोफाइनेंस रिव्यू'' शीर्षक से एक अर्ध्य वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है, इसके जुलाई–दिसम्बर 2016 के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित तीन विषयो पर अधिक कार्य किया गया है।

1. एस एच जी बैंक लिंकेज कार्यक्रम– मुद्दे तथा भावी योजनाएँ
2. सूक्ष्म वित संस्थाओं (एम एफ आई) का संस्थागत विश्लेषण – स्थिति एवं सूक्ष्म वित्तसंस्थों की व्यापक और ज्यादा प्रभावी पहुँच के लिए उपाय व स्थिति।
3. भारत में सूक्ष्म वित के सामाजिक और सशक्तिकरण संबंधी पहलू–साक्ष्य।

लखनऊ मण्डल के द्वारा नाबार्ड के साथ कार्य करने की बहुत अधिक भूमिका रही तथा ग्रामीण स्तर पर बहुत सहायता युक्त कार्य किये गये।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ऋण की व्यवस्ता करना।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण की सुविधा प्रदान कराना।
3. स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्रामीणों तक सहायता पहुचाना।
4. ग्रामीण स्तर पर उद्योगो के लिए ऋण की व्यवस्था करना।

नाबार्ड का कारोबार 11505 करोड़ से अधिक

लखनऊ यूपी में नाबार्ड का कारोबार पिछले वर्ष की अपेक्षा 11505 करोड़ से अधिक रहा। नाबार्ड के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय का राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण विकास बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण वितरण, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण तथा राज्य में कम समय में सहकारी ऋण संरचना का सुदृढीकरण इस दिशा में उसके विशेष प्रयास रहे हैं। नाबार्ड राज्य में इसके अलावा भी कई अन्य नई पहलों का सूत्रधार रहा है। यूपी में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय गोमतीनगर लखनऊ में है।

शोध/अनुसंधान की प्रविधियॉ/उपकरण

अनुसंधान कार्य के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों का विशलेषण करने के हम अनुसंधान के समय जिन प्रविधियों का प्रयोग करतें है वह निम्नलिखित है–

अनुपात विश्लेषण

अनुपात विश्लेषण के अन्तर्गत हम वित्तीय विवरणों में सभी मदों जो प्रयोग हुई है का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण के अन्तर्गत किया जाता है जो निम्नप्रकार है–

अनुपात विश्लेषण का अर्थ

वित्तीय विवरणों में व्यक्त संख्याएँ एवंत थ्य मूक होते हैं, अनुपातो का प्रयोग उन्हें सरल, शीघ्र, एवं समझने योग्य होने के कारण अनुपात विश्लेषण दिनों–दिन प्रबन्ध एवं व्यावसायिक क्षेत्र में काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इस तकनीक से एक दी हुई अवधि में विभिन्न अन्तरों पर निकाले गए अनुपात व्यवसाय की प्रगति या अवनति को प्रदर्शित करते है।

हैलफर्ट के अनुसार–''अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक उच्च या निम्न कार्यक्षमता तथा किसी औसत या तुलनात्मक प्रमाप से महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी के लिए संकेत या मार्गदर्शक का कार्य करता है.''

अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता

1. पूर्वानुमान में सहायक
2. मानक निर्धारण में सहायक
3. वित्तीय क्षमता के मूल्यांकन में सहायक
4. कार्यकुशलता के मूल्यांकन में सहायक
5. संस्था में रूचि रखने वाले पक्षों का लाभ
6. योजनाएँ निर्धारण में सहायक
7. सूचनाओं के संवहन में सहायक
8. प्रभावी नियत्रण सत्भव

अनुपात विश्लेषण का वर्गीकरण

अनुपातों का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, किन्तु इन्ही अनुपातों का प्रयोग सबसे उपयोगी होता है, जो उद्दश्यो के अनुरूप हो, इसमें सम्लित सूचनाओं के आधार पर अनुपात निकाले जाते है, क्यो कि लेखा सम्बन्धी सूचनाए दो विवरणों 1.आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) 2. लाभ–हानि खाता (Profit & Loss A/c) से प्राप्त की जाती है, इसलिए अनुपातों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है.

वित्तीय विवरण के आधार पर अनुपात

आर्थिक चिट्ठा अनुपात (Balance Sheet Ratio)

1. चालू अनुपात (Current Ratio)
2. स्कन्ध अनुपात (Stock Ratio)
3. तरलता अनुपात (Liquidity Ratio)
4. स्वामित्व अनुपात (Proprietary Ratio)

लाभ–हानि अनुपात (Profit & Loss Ratio)

1. आय अनुपात (Earning Ratio)
2. व्यय अनुपात (Expenses Ratio)
3. बिक्री अनुपात (Sales Ratio)

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-8* April- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
प्रधान कार्यालयः प्लॉट सं0 सी–24, जी ब्लॉक, बॉद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई–400051, बेवसाइटः www.nabard.org
Head Office: Plot No. C-24, G Block] Bandra-Kurla Complex] Bandra (E) Mumbai 400051, Website: www.nabard.org

31 मार्च 2020 को समाप्त वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम
Audited Financial Result for the year ended March 31, 2020 (करोड़ में) (in crore)

क्रम सं. **Sr. No.**	विवरण **Particulars**	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित **Year ended 31 March 2019 Audited**	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित **Year ended 31 March 2020 Audited**	परिवर्तनशीलता **Variance**
1	अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ) Interest earned (a)+(b)+(c)+(d)	29,602.62	32,611.26	3,008.64
(क) (a)	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज Interest on Loans and advance	26,248.71	28,744.66	2,495.95
(ख) (b)	निवेशों पर आय Income on investments	3,353.91	3,866.60	512.69
(ग) (c)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष रकम तथा अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	0.00	0.00	0.00
(घ) (d)	अन्य Others			
2	अन्य आय Other Income	0.00	0.00	0.00
3	कुल आय (1+2) Total Income (1+2)	65.29	81.04	15.75
4	व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	29,667.91	32,692.30	3,024.39
5	परिचालन व्यय (i)+(ii) Oprating Expenses (i)+(ii)	22,198.72	23,782.98	1,584.26
(i)	कर्मचारियों पर लागत Employees cost	1,987.57	2,275.07	287.50
(ii)	अन्य परिचालन व्यय Other operating expenses	1539.15	1,814.81	275.66
		448.42	460.26	11.84

6	कुल व्यय (4+5) प्रावधान तथा आकस्मिताओं रहित **Total Expenditure (4+5) excluding provisions and contingencies**	**24,186.29**	**26,058.05**	**1,871.76**
7	प्रावधान तथा आकस्मिताओं से पूर्व परिचालन लाभ (3-6) **Oprating Profit before Provisions and contingencies (3-6)**	**5,481.62**	**6,634.25**	**1,152.63**
8	प्रावधान (कर के अतिरिक्त) और आकस्मिताएँ Provisions (Other than tax) and Contingencies	522.27	1,399.93	877.66
9	अपवादात्मक मदें Exceptional Items	0.00	0.00	0.00
10	कर से पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (+)/ हानि (-) (7-8-9) **Profit (+)/Loss (-) from Ordinary Activities before tax (7-8-9)**	**4,959.35**	**5,234.32**	**274.97**
11	कर व्यय Tax Expenses	1,594.79	1,375.09	-219.70
12	कर के पश्चात (10-11) सामान्य कार्यकलापों से शुद्ध लाभ (+)/हानि(-) **Net Profit (+)/Loss(-) from Ordinary Activities after tax (10-11)**	**3,364.56**	**3,859.23**	**494.67**
13	असाधारण मदें (कर व्यय को घटाने के बाद) Extraordinary items (net of tax expense)	0.00	0.00	0.00
14	अवधि (12-13) के लिए निवल लाभ (+)/ हानि (-) **Net Profit (+)/Loss(-) for the period (12-13)**	**3,364.56**	**3,859.23**	**494.67**
15	प्रदत्त पूंजी Paid-up capital			
16	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर प्रारक्षित निधियॉ Reserves excluding Revaluation Reserves	12,580.00	14,080.00	1,500.00
17	विश्लेषणात्मक अनुपात **Analytical Ratios**	30,688.75	34,410.99	3,722.24
(i)	पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio			
(ii)	प्रति शेयर आय Earnings Per Share (EPS)			
18	निवल अनर्जक आस्ति अनुपात **NPA Ratio**	18.96%	21.20%	2.24%
(क) (a)	सकल अनर्जक आस्तियॉ Gross NPA	NA	NA	NA

(ख) (b)	निवल अनर्जक आस्तियॉ Net NPA			
(ग)	सकल ऋण और अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	168.06	1,236.99	1,068.93
(c)	% of Gross NPA to Gross Loans & advances	0.00	719.88	719.88
(घ)	निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	0.0389	0.2565	0.2176
(d)	% of Net NPA to Net loans & advances			
19	**आस्तियों पर प्रतिफल (रिटर्न)** **Return on Assets**	0.0000	0.1494	0.1494
		0.76%	**0.79%**	**0.03%**

NA = Not Applicable Return on Assets = Net Profit (after tax) divided by total average assets

Notes:

1. The above result were reviewed by audit committee of the Board and approved by Board of Directore at its meeting held on 22th may 2020 at Mumbai.
2. Provisions and contingencies includes Floting Provision of Rs.500 crore created during the year.
3. During the year GOI contributed Rs.1500 crore towards the capital of NABARD.
4. The management of the Bank assessed the impact of the COVID19 considering its internal and External input for ascertaining the same on the financial reporting number in the opinion of the management of the Bank, such impact on the reported number would not be significant.
5. Previous period figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

Place: Mumbai
Date: 22 May 2020

Harsh Kumar Bhanwala
Chairman

पिछले कुछ वर्षो के दौरान कृषि क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसमें नाबार्ड की भूमिका रही है।

1. नाबार्ड ने बहुत सारी सकारात्मक गतिविधियों को अपनाया है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में आवश्यक संरचनागत परिवर्तनो की उम्मीद जागी है। इनमें मुख्यतः फसल विविधीकरण, वैज्ञानिक कृषि पद्वति अपनाना, भंडारण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण आदि शामिल है। नाबार्ड ने देश में 1.27 लाख कृषक क्लबों का नेटवर्क तैयार किया है। जो किसानो को बेहतर कृषि पद्वति अपनाने की आवश्यकता एक साथ आने और संगठित विपणन के लाभ के बारे में किसानो को शिक्षित कर रहे है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण भंडारण योजना नाबार्ड के माध्यम से परिचालित की जा रही है। इसमें भंडारण क्षमता बढ़ गई है। और इस प्रकार की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं के बारें में जागरूकता बढ़ी है। किसानो द्वारा भंडारण में रखे गए उपज के आधार पर कर्जा भी मिल रहा है। इससे किसानो को कम दाम पर अपने उपज को बाध्य नही होना पड़ेगा।
2. किसान तकनीकी अंतरण निधि के अन्तर्गत मुख्य फसलों हेतु प्रायोगिक परिवर्तन सिस्टम ऑफ राइस इन्टेन्सिफकेशन (एस0आर0आई0) मास्टर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास कार्यक्रम, कृषक क्लब कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्षमता निर्माण (सी0ए0टी0) कृषकों को प्रशिक्षण और ग्रामीण केन्द्र (एफ0टी0आर0डी0सी0) आदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं से नाबार्ड पिछले कुछ वर्षो में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
3. वाटरशेड वाडी आदि पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कारण नाबार्ड जलवायु परिवर्तन अपनाने के परियोजनाओं को भी बढ़े पैमाने पर अपना रहा है। इसी सन्दर्भ में हाल ही में नाबार्ड जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू0एन0एफ0सी0सी0) के क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत स्थापित एडाप्टेशन फंड बोर्ड (ए0एफ0बी0) का राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था (एन0आई0) के रूप में नामित किया गया है।

सम्बन्धित शोध–साहित्य

मलहोत्रा (2002) ने 22 अलग–अलग पैरामीटरो को माना जो प्रभावित हुये। वर्ष 2000 के लिए आरआरबी के कामकाज से मलहोत्रा ने दावा किया कि आरआरबी के स्थान उनके भौगोलिक प्रदर्शन के लिए सीमित कारक नही है। उन्है आगे पता हैकि प्रायोजित बैंक अपने प्रदर्शन के लिए कार्डीनल है।

राव (2002) ने बैंकिंग क्षेत्र पर नई तकनीक के प्रभाव का विश्लेषण किया, टैक्नोलॉजी कारोबार के तरीके को बदलती है। और एक ही काम को अलग तरीके से करवाने के लिए नये लागत प्रभावी रास्ते बताती है।

नितिन और थोरट (2004) एक मर्मज्ञ विश्लेषण प्रदान करते है। कि कैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थागत आयाम ने गवर्नेस को गंभीरता से बिगाड़ दिया है। उन्होने तर्क दिया है कि राजनैतिक जैसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारों के लिए प्रतिकूल संस्थागत व्यवस्थाएँ दी है। नेताओ की नीति निर्माता बैंक कर्मचारियों और तत्वो ने बाधाओ के रूप में कार्य किया है। उनका प्रदर्शन प्रोतसाहन संरचनाओं में वृद्वि करना था।

सतीश (2006) ने पंजाब में कृषि में संकट की समीक्षा की, उन्होने कहा कि बैंको का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रान्ति, कृषि के लिए संस्थागत ऋण सहित होने चाहिए। पंजाब में उगाया गया अनाज विकास के समान नही था और इस तरह की मॉग अनुरूप ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य में ऋणी भी बढ़ी है, लेकिन कर्ज का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए नही दिया गया। अखिल भारतीय औसत और अध्ययन से पता चलता है कि ऋणदाता वास्तव में एक प्रमुख है।

महाराष्ट्र में एक अध्ययन में, काले (2011) ने पाया कि कम उत्पादकता, कम वार्षिक आय, आय देयता अन्तर, ऋणग्रस्तता और गैर–संस्थागत ऋण प्राप्त करने का अस्तित्व नही है। और महाराष्ट्र में आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारणों के रूप में साबित हुआ है। कृषि के लिए बढ़ी हुई संस्थागत ऋण की आवश्यकता को स्वीकार करतें हुये, सरकार ने देश की स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत ने कई नीतिगत उपायों की शुरूआत की। एक परिणाम के रूप में देश में संस्थागत ऋण संरचना दोनों मात्रा में एक महत्वपूर्ण वृद्वि दिखायी है। और पिछले कुछ दशको में जटिलता एक व्यापक बैंकिंग है। वाणिज्य बैंकों की 33,411 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओ वाली एक बुनियादी के रूप में है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14501 शाखाएँ है। और जिला केन्द्र में करीब 12000 शाखाएँ है, और लगभग 1,00,000 सहकारी क्रेडिट सोसायटी गॉव स्तर पर है जो लगभग 5000 ग्रामीण लोगो या 1000 के लिए कम से कम एक क्रेडिट आउटलेट में अनुवाद करता है।

विशेषज्ञ समित द्वारा जारी रिपोर्ट (2013) इस विशेषज्ञ समिति को आरबीआई द्वारा नामित किया गया था। यह समिति नाबार्ड के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी की अध्यक्षता में गठित हुई। विशेषज्ञ समिति को तीन स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना पर आईएनए की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें निम्न जॉच करनी थी। अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनर्वित्त की जॉच करना और बी STCCS के समेकन के लिए उपयुक्त तंत्र का सुझाव देना और हितधारकों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। विशेषज्ञ समिति के द्वारा किये गये अवलोकन के बाद विशेषज्ञ समिति ने माना कि कृषि ऋण की आपूर्ति में अल्पकालीन सहकारी समितियों का हिस्सा घटकर कुल 14% रह गया। समिति का विचार था कि मुख्य रूप से एसटीसीसीएस का गठन किया जाये जो क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करे और धीरे–धीरे इसे 30% तक बढ़ाये। समिति ने यह भी सिफारिश की यदि कोई सीसीबी या एससीबी लगातार अंडरपरफॉर्म करता है और परिचालन क्षेत्र में ऋण कुल कृषि का 15% से कम प्रदान करता है तो ऐसे बैंक को शहरी सहकारी बैंक घोषित किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय योजना (2012–17) में डा0 वाई.एस.पी. थोरट (नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष) की अध्यक्षता में ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्किग ग्रुप का गठन किया गया। 12 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्व क्षेत्र, सबसेंटर विश्लेषण करके पूरे देश में उचित दर पर ऋण प्रवाह करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए भी निर्देशित किया गया। समूह ने देखा कि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के बाद अल्पकालिक सहकारी ऋण प्रदान करने के बाद उनके लाभ और परिणामस्वरूप उनके बढ़ते घाटे में गिरावट शुरू हुई। समूह ने पाया कि एसटीसीसीएस के बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य के बावजूद कृषि ऋण में उनकी हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई। वर्किग ग्रुप के अनुसार, गरीब संसाधन आधार, गरीब प्रबंधन, अकुशल शासन और सक्रिय सदस्यों की कमी ऋण प्रवाह में महत्वपूर्ण बाधाएं थी।

नोटः–लेखक की जानकारी के अनुसार साहित्य अवलोकन 2017 तक ही प्राप्त किया गया है।

शोध की वर्तमान समय में प्रासंगिकता

वर्तमान समय में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेतें हुये नाबार्ड बैंकों की वित्तीय विवरण की समस्या का निस्तारण करना है। क्यो कि नाबार्ड बैंक की वित्तीय स्थिति सही होगी, तो ग्रामीण लोगों कों तथा ग्रामीण किसानों को अधिक सुविधाएँ मिल सकेगीं। और ग्रामीण स्तर पर संचालित उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए नाबार्ड बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कम ब्याज पर अधिक ऋण की व्यवस्था करनी होगी। तथा ग्रामीण स्तर पर लोगों की बेरोजगारी स्थिति केा सुधारने के लिए नाबार्ड बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नई पद्वतियों उपयोग करना होगा।

निष्कर्ष

नाबार्ड भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण एवं ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु एक सर्वोच्च संस्थान है। यह ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण एवं गरीबी कम करने हेतु समर्पित है। आयोजना प्रक्रिया के आरंभिक चरण से ही भरत सरकार की यह स्पष्ट धारणा रही है, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार द्वारा कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे जनता या किसान विचौलियों से बच सके जो ये बीच में ही आधा पैसा खा जाते ह। नाबार्ड द्वारा जो ये ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी रणनीति अपनाये जिससे जनता एवं किसानों को ऋण सुविधा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ सीधा इन लोगो को मिल सके। इस प्रकार से तो ग्रामीण विकास हर हाल में सम्भव होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *https://hi.wikipedia.org/wiki*
2. *https://www.jagranjosh.com/general*
3. *https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/lucknow/storynabard-1115874.html*
4. *https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/current+affairs+todayepaper-curast/nabard+sanstha+kya+hainewsid-n227*
5. *वेबसाइटः http:/www.birdlucknow.in*
6. *दिशानिर्देश*
7. *वेबसाइटःhttp://www.birdlucknow.incenter-of-excellence/cmr/microfinance-review-journal/.*
8. *नाबार्ड वेबसाइटः (nabard-websites.aspx)*